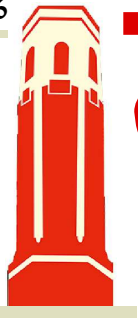


- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 271
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

अकिता भंडारी हत्याकांड

राठौड़ नार्को टेस्ट को तैयार, उर्मिला पहुंची सीबीआई कोर्ट



हमारे संवाददाता

देहरादून। बहुचर्चित अकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की पहचान को लेकर जारी चर्चाओं के बीच आज पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने नार्को टेस्ट कराने के लिए अपनी सहमति जताई। वह देहरादून स्थित सीबीआई कोर्ट पहुंचे और मीडिया के सामने सहमति से संबंधित पत्र भी दिखाया। इसी मामले में कथित वीआईपी से जुड़े दावों की जांच के सिलसिले में उर्मिला सनावर भी सीबीआई

कोर्ट पहुंचीं।

मामले में हाल के दिनों में वायरल ऑडियो और उससे जुड़े दावों के बाद एक बार फिर हलचल तेज हुई है। कथित वीआईपी की पहचान को लेकर उठ रहे सवाल के बीच अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई और संबंधित लोगों के बयानों पर नजर बनी हुई है। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति जताते हुए जांच एजेंसियों को सहयोग देने की बात कही। मीडिया

से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह जांच में हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगाए हैं। हालांकि, वायरल ऑडियो से जुड़े सवालों पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। राठौड़ की ओर से सहमति जताए जाने के बाद मामले में आगे की जांच को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, नार्को टेस्ट की प्रक्रिया और उससे संबंधित

आगे की कार्रवाई के बारे में स्थिति जांच एजेंसियों एवं न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही स्पष्ट होगी।

वहीं, कथित वीआईपी से जुड़े दावों की पड़ताल के बीच उर्मिला सनावर भी आज सुबह सीबीआई कोर्ट पहुंचीं। बताया गया है कि नार्को टेस्ट की प्रक्रिया के संबंध में उन्हें अदालत की ओर से नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट पहुंचने के बाद उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें सहयोग नहीं कर रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के लिए समय मांगे जाने की बात भी कही। उनके पहुंचने से पहले सुरेश राठौड़ कोर्ट परिसर से निकल चुके थे। अकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की पहचान को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। हालिया घटनाक्रम में सुरेश राठौड़ की नार्को टेस्ट के लिए सहमति और उर्मिला सनावर के सीबीआई कोर्ट पहुंचने से मामला फिर चर्चा में है।

दूनघाटी में महिला जज भी 'असुरक्षित'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जब एक महिला न्यायाधीश की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाएं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी के दावों, पुलिस की मुस्तैदी के बखान और कानून-व्यवस्था के सरकारी भरोसों के बीच राजधानी की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा आखिर कहां खड़ी है? महिला न्यायाधीश के साथ कथित अभद्रता, धमकी, छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास का मामला सामने आने के बाद पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

देहरादून में तैनात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-5 ने डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, एक रैपिडो चालक ने तय किराये से दोगुने पैसे मांगे। आरोप है कि इसके

बाद चालक उन्हें सुनसान और अंधेरे रास्ते की ओर ले गया तथा धमकाने और गलत इरादे से व्यवहार करने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह मामला महज किराये को लेकर हुए विवाद तक सीमित नहीं है। शिकायत में जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वह राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यदि यात्रा के लिए बुक की गई सेवा ही किसी महिला के लिए भय और असुरक्षा का कारण बनने लगे, तो फिर सुरक्षा के दावों की हकीकत पर सवाल उठना लाजिमी है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि मामला न्यायपालिका से जुड़ी एक महिला अधिकारी का है। जब कानून की रक्षा करने वाली व्यवस्था से जुड़ी महिला को ही ऐसी

परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो आम महिला के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी,

◆ दून में वर्दी का खौफ खत्म, सड़कों पर बेखौफ अपराधी
◆ महिला जज से अभद्रता, धमकी, अपहरण की कोशिश
◆ मामले से खुली राजधानी की कानून-व्यवस्था की पोल

लेकिन घटना ने पुलिस की जवाबदेही का सवाल जरूर सामने ला दिया है। राजधानी में पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी अपराध होने के बाद आरोपी को तलाशना ही नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार करना भी है। सवाल यह है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से

जुड़े चालकों के सत्यापन, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और महिलाओं की आपातकालीन सुरक्षा के इंतजाम कितने प्रभावी हैं?

अगर पुलिस केवल प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपी की तलाश शुरू करने तक सीमित रह जाती है, तो महिलाओं में भरोसा कैसे कायम होगा? जरूरत इस बात की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच की जाए और शिकायत में लगाए गए प्रत्येक आरोप की गंभीरता से पड़ताल हो। देहरादून तेजी से फैलता शहर है। आबादी बढ़ रही है, यातायात का दबाव बढ़ रहा है और सार्वजनिक परिवहन के नए माध्यम भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को भी उसी अनुपात में मजबूत होना चाहिए। लेकिन महिला न्यायाधीश से जुड़े इस मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजधानी की

सुरक्षा व्यवस्था बदलते शहरी हालात के अनुरूप तैयार है?

महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकारी विज्ञापनों, बैठकों और दावों से सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए सड़कों पर प्रभावी पुलिस गश्त, संवेदनशील इलाकों में निगरानी, परिवहन सेवाओं के चालकों का सत्यापन और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है। देहरादून में महिला न्यायाधीश से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई अब पुलिस की कसौटी है। राजधानी की महिलाओं को भरोसा चाहिए कि उनकी सुरक्षा केवल कागजों और दावों तक सीमित नहीं है। सवाल सिर्फ एक महिला अधिकारी का नहीं, बल्कि उस हर महिला का है, जिसे देहरादून की सड़कों पर बिना किसी डर के सफर करने का अधिकार है।

दून वैली मेल

संपादकीय

बंगाल की खाड़ी में हलचल

समुद्र की लहरों में उठने वाली हलचल केवल तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहती। कई बार उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। बंगाल की खाड़ी में मौसम संबंधी गतिविधियों का तेज होना भी ऐसी ही चेतावनी है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, कम दबाव के क्षेत्रों और मानसूनी प्रणालियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां इस समुद्री क्षेत्र को विशेष रूप से संवेदनशील बनाती हैं। यहां पैदा होने वाली मौसमी उथल-पुथल पूर्वी और दक्षिणी भारत के साथ मध्य भारत तथा हिमालयी क्षेत्रों के मौसम को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में होने वाले बदलावों पर निगाह रखना केवल मौसम विज्ञान की जरूरत नहीं, बल्कि जनजीवन और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा का भी प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तट पर बड़ी आबादी निवास करती है और करोड़ों लोगों की आजीविका मत्स्य पालन, कृषि, समुद्री व्यापार तथा पर्यटन से जुड़ी है। समुद्र में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र जब मजबूत होता है तो वह चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। तेज हवाएं, भारी वर्षा, समुद्र में ऊंची लहरें और तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए ऐसी परिस्थितियां विशेष सतर्कता की मांग करती हैं। प्रकृति के इन संकेतों को केवल मौसमी घटनाक्रम मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन के दौर में मौसम की अनिश्चितता बढ़ने और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाओं के जोखिम को लेकर चिंता गहरी हुई है। हालांकि हर चक्रवात या कम दबाव की घटना को जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम नहीं माना जा सकता, लेकिन बदलती जलवायु के प्रभावों को समझना और उनके अनुरूप तैयारी करना अब अनिवार्य है। समुद्र की सतह का तापमान, वायुमंडलीय परिस्थितियां और हवाओं की दिशा किसी भी मौसमी प्रणाली की तीव्रता तथा उसके मार्ग को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अनुमान और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को समझते हुए वैज्ञानिक चेतावनियों पर भरोसा करना जरूरी है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन की तैयारियों का महत्व बढ़ जाता है। समय रहते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह देना, तटीय बस्तियों में चेतावनी प्रणाली मजबूत करना, जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और राहत शिविरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल चेतावनी जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। उसका समय पर संबंधित लोगों तक पहुंचना और उस पर अमल सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। स्थानीय प्रशासन, मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसियों और समुदायों के बीच बेहतर तालमेल से जनहानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसका एक आर्थिक पक्ष भी है। चक्रवाती परिस्थितियां समुद्री परिवहन, बंदरगाहों, कृषि उत्पादन और मछुआरों की आजीविका को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में आपदा के बाद राहत देने के साथ-साथ पहले से जोखिम कम करने की नीति अपनानी होगी। तटीय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक सुरक्षा कवचों का क्षरण नुकसान को बढ़ा सकता है। विकास की योजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन और आपदा जोखिम को पर्याप्त महत्व देना समय की मांग है। बंगाल की खाड़ी में उठती हलचल का संदेश स्पष्ट है। प्रकृति के सामने मनुष्य की सीमाएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक समझ, समयबद्ध तैयारी और जिम्मेदार प्रशासन के माध्यम से नुकसान को कम किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर आपदा के बाद चेतने के बजाय उसके आने से पहले तैयारी करें। समुद्र की चेतावनी को सुनना और उसे जनसुरक्षा की ठोस रणनीति में बदलना ही समझदारी है।

परम संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने हजारों संगत को दर्शन देकर निहाल किया

संवाददाता

काशीपुर। विश्व धर्म संघ और सावन कृपाल रूहानी मिशन के अध्यक्ष परम संत राजिन्दर सिंह महाराज ने बृहस्पतिवार को कृपाल आश्रम काशीपुर में हजारों संगत को दर्शन देकर निहाल किया। 9 साल बाद संत राजिन्दर सिंह महाराज जी काशीपुर पहुंचे। यहां गढ़ी नेकी रोड पर कुंडा चौराहे के पास स्थित कृपाल आश्रम में महाराज जी ने संगत के बीच जाकर संगत को निहाल किया।



इस दौरान सत्संग समागम में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से हजारों संगत पहुंची। इस अवसर पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, संदीप सहगल, मिशन के स्थानीय अध्यक्ष परमजीत सिंह, सचिव रंजीत सिंह, जसपाल सिंह, सिमरनजीत सिंह आदि मौजूद थे।

सत्संग के पश्चात रात 9 बजे आध्यात्मिक दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें संत राजिन्दर सिंह जी महाराज जिज्ञासुओं को प्रभु की ज्योति व श्रुति का निजानुभव प्रदान करेंगे। वहीं देर रात सावन कृपाल रूहानी मिशन के अध्यक्ष परम संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने कृपाल आश्रम गौतम नगर के अलावा ठाकुरद्वारा, असदुल्लाहपुर आश्रम में पहुंचकर संगत को दर्शन

►► शेष पृष्ठ 7 पर

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक मोर्चेबंदी तेज कर दी है। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के जरिए भाजपा विपक्ष को घेरने और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस की न्याय यात्रा से लेकर विधानसभा घेराव तक को भाजपा जहां राजनीतिक हताशा से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में मुद्दों की लड़ाई अब आरोपों और प्रत्यारोपों के नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है।

भाजपा के लिए यह अभियान केवल कांग्रेस के विरोध का कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक विमर्श की दिशा तय करने की कोशिश भी है। पार्टी चाहती है कि चुनावी बहस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ विपक्ष के आरोपों तक सीमित न रहे, बल्कि कांग्रेस के आंदोलनों, उसके राजनीतिक आचरण और विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठें। कांग्रेस प्रदेश में न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार को घेरने में जुटी है। भाजपा इन आंदोलनों को जनसमस्याओं के समाधान की लड़ाई के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन करार दे रही है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जनता के सवालों का

ठोस समाधान नहीं दे पाई और अब आंदोलनों के जरिए राजनीतिक जमीन तलाश रही है।

भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से अधिक राजनीतिक टकराव में दिलचस्पी है। हालांकि, विपक्ष के आंदोलनों को केवल राजनीतिक नाटक बताने से उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, जिन्हें लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। यही वह मोर्चा है, जहां भाजपा को अपने आरोपों के साथ सरकार के

◆ विस चुनाव से पहले कांग्रेस पर हमलावर हो गई है भाजपा
◆ सियासी संग्राम को सड़क से सदन तक ले जाने की तैयारी
◆ कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश

कामकाज और उपलब्धियों का हिसाब भी जनता के सामने रखना होगा। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ जैसे नारे के जरिए भाजपा कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरना चाहती है। इस संदेश में विपक्ष के आंदोलनों को अराजकता से जोड़ने और सत्तारूढ़ दल को लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर के रूप में पेश करने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना, जनसमस्याओं पर सवाल उठाना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार भी है।

ऐसे में अभियान की राजनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भाजपा विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई किसी

कथित अव्यवस्था के ठोस तथ्य सामने रख पाती है या फिर यह अभियान केवल चुनावी नारेबाजी तक सीमित रह जाता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दोनों पक्षों की जवाबदेही है कि वह राजनीतिक विरोध और अराजकता के बीच का अंतर स्पष्ट रखें। उत्तराखंड में भाजपा के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती है, जबकि कांग्रेस सरकार को घेरकर सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी है। भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है। दूसरी ओर कांग्रेस आंदोलनों के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना चाहती है।

इसी टकराव के बीच भाजपा का नया अभियान चुनाव से पहले विपक्ष की धार कुंद करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को जनता के सामने अपने आंदोलनों का औचित्य साबित करना पड़े। वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह अपने विरोध प्रदर्शनों को केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन तक सीमित न रखकर जनता के ठोस सवालों से जोड़कर रखे। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के अभियान तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन जनता के लिए नारों से ज्यादा महत्व उन समस्याओं का है, जिनसे उसका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भ्रष्टाचार और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं

►► शेष पृष्ठ 7 पर

...और भाजपा को याद आई ‘वोट चोरी’

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। अब तक कांग्रेस जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाती रही है, वहीं भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाकर पलटवार शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर छिड़ी यह जुबानी जंग अब राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बनती दिख रही है। सवाल यह है कि मतदाताओं के अधिकारों की चिंता करने वाले राजनीतिक दलों की प्राथमिकता वास्तव में पारदर्शी चुनाव व्यवस्था है या फिर मतदाता सूची के बहाने एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की सियासी कवायद?

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बड़ी संख्या में नाम हटने और नए नाम जुड़ने के आंकड़ों ने राजनीतिक दलों को आमने-सामने ला दिया है। कांग्रेस लगातार मतदाता सूची में नाम काटे जाने को लेकर सवाल उठाती रही है। पार्टी की आशंका है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया का असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश के रूप में पेश कर रही है और अब खुद भी वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष को घेर रही है।

मतदाता सूची में संशोधन निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब बड़े

पैमाने पर नाम हटने की बात सामने आए तो यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे। इसी तरह राजनीतिक दलों को भी आरोप लगाने से पहले ठोस तथ्य सामने रखने चाहिए। केवल राजनीतिक बयानबाजी से न तो किसी का आरोप साबित होता है और न ही

◆ कांग्रेस पर हमलावर हुई भाजपा, मतदाता सूची के विवाद ने पकड़ा सियासी गूल
◆ भाजपा ने शुरु कर दिया है कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाकर पलटवार
◆ यह दलों की जुबानी जंग अब राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बनती दिख रही

मतदाताओं की शंकाओं का समाधान। भाजपा नेताओं की ओर से कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप ऐसे समय लगाए जा रहे हैं, जब दोनों दलों ने 2027 की चुनावी लड़ाई के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में जुटी है। कांग्रेस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मतदाता सूची का विवाद दोनों दलों के लिए एक-दूसरे पर राजनीतिक बढ़त बनाने का माध्यम बनता दिखाई दे रहा है।

भाजपा की रणनीति कांग्रेस को रक्षात्मक स्थिति में लाने की हो सकती है, जबकि कांग्रेस मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंकाओं को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर उठा रही है। मगर इस राजनीतिक

टकराव के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल पीछे छूटना नहीं चाहिए कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं, उनमें कितने अपात्र थे और कितने पात्र मतदाताओं के नाम किसी त्रुटि के कारण कटे हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े आंकड़े चुनावी बहस का केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को आंकड़ों की अपनी-अपनी व्याख्या करने के बजाय उन मामलों को सामने लाना चाहिए, जिनमें कथित गड़बड़ी हुई है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसकी बहाली सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं, यदि किसी राजनीतिक दल के पास वोट चोरी के प्रमाण हैं तो उन्हें संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लोकतंत्र में मतदाता सूची की विश्वसनीयता चुनाव की निष्पक्षता की बुनियाद है। इस पर संदेह पैदा करने वाले आरोप गंभीर हैं और उनका निपटारा भी तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाकर राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला जैसे-जैसे नजदीक आएगा, वैसे-वैसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के और तीखे होने की संभावना है। भाजपा सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। मतदाता सूची का विवाद अब इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है।

►► शेष पृष्ठ 7 पर

अकिता केस पर चुनावी रण की आहट

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासत के केंद्र में आता दिख रहा है। न्याय की मांग को लेकर उठती आवाजों और राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने इस प्रकरण को फिर गरमा दिया है। संकेत हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सड़क से सदन तक गूँज सकता है। विपक्ष जहां इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़कर चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, वहीं भाजपा के सामने इस मामले में उठ रहे सवाल का जवाब देने और जनता के बीच अपना पक्ष मजबूती से रखने की चुनौती है।

अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड में केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है। यह महिला सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े सवालों का प्रतीक बन चुका है। मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठती मांगों और सीबीआई जांच से जुड़ी चर्चाओं ने इस प्रकरण को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाए रखा है। ऐसे में चुनाव से पहले इस मुद्दे का फिर उभरना प्रदेश की राजनीति में नए टकराव की जमीन तैयार कर सकता है।

अंकिता के माता-पिता की ओर से

न्याय की मांग और मामले से जुड़े शेष सवालों को लेकर उठती आवाजें राजनीतिक दलों के लिए भी अहम हो गई हैं। हाल के घटनाक्रम में अंकिता के माता-पिता को दिल्ली में इंडिया गेट पर धरना शुरू करने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस घटनाक्रम ने मामले को



प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी चर्चा में ला दिया। विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का नया आधार मिला है, जबकि सत्तारूढ़ दल के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह जांच और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष स्पष्ट करे।

कांग्रेस पहले से ही इस प्रकरण को लेकर भाजपा पर हमलावर रही है। पार्टी का जोर इस सवाल पर है कि यदि दोषियों को सजा मिल चुकी है, तो कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों का अंतिम और स्पष्ट जवाब कब मिलेगा? कांग्रेस इस मुद्दे को महिला सम्मान, न्याय और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों से

जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, आरोपों और आशंकाओं को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। मामले में जो कुछ न्यायिक रूप से स्थापित है और जो जांच के दायरे में है, दोनों के बीच अंतर बनाए रखना भी जरूरी है।

भाजपा के लिए अंकिता प्रकरण इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में महिला सम्मान और पहाड़

◆2027 के चुनाव से पहले फिर गरमाएगा अंकिता भंडारी प्रकरण ◆न्याय की मांग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति में विपक्ष ◆सड़कों से विधानसभा तक उठ सकता है अंकिता का यह मुद्दा

की बेटी को न्याय दिलाने का भाव व्यापक जनभावनाओं से जुड़ा है। पार्टी के नेता पहले भी कांग्रेस पर इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा का तर्क रहा है कि सरकार ने एसआइटी गठित कर जांच कराई और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन विपक्ष का संभावित सवाल इससे आगे का है। क्या मामले से जुड़े सभी सवालों का संतोषजनक जवाब मिल गया है?

यही वह बिंदु है, जहां सरकार का प्रशासनिक पक्ष और विपक्ष का राजनीतिक हमला आमने-सामने आ सकते हैं। सरकार के लिए केवल पूर्व में की गई कार्रवाई गिनाना पर्याप्त नहीं होगा। उसे जांच की वर्तमान स्थिति और कानूनी प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों को स्पष्टता से सामने रखना

होगा। दूसरी ओर, विपक्ष को भी आरोपों की राजनीति से आगे बढ़कर तथ्यों और जवाबदेही के आधार पर अपनी बात रखनी होगी।

यदि अंकिता प्रकरण को लेकर आंदोलन तेज होता है, तो विधानसभा के आगामी सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। विपक्ष सरकार से जांच की स्थिति, सीबीआई की भूमिका और कथित वीआइपी से संबंधित सवालों पर जवाब

मांग सकता है। सदन के भीतर सवाल, स्थगन प्रस्ताव या अन्य संसदीय माध्यमों से सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, इस मुद्दे पर किसी औपचारिक रणनीति या कार्यक्रम की घोषणा होने तक इसे संभावित राजनीतिक दिशा के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

सड़क पर आंदोलन और सदन में सवालों का दबाव एक साथ बना, तो सरकार के लिए राजनीतिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर तब, जब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रहने पर हर बड़ा मुद्दा जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। अंकिता प्रकरण में भावनात्मक पहलू भी मजबूत है, इसलिए राजनीतिक दलों की रणनीति का असर उनके समर्थकों से आगे व्यापक मतदाता

वर्ग पर पड़ सकता है।

2027 के चुनाव में अंकिता भंडारी हत्याकांड कितना प्रभाव डालेगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह मुद्दा भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन सकता है। कांग्रेस इसे सरकार की जवाबदेही का सवाल बनाना चाहेगी, जबकि भाजपा की कोशिश होगी कि मामले में हुई कार्रवाई को सामने रखकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग राजनीतिक नारेबाजी तक सीमित न रह जाए। परिवार के सवालों का तथ्यात्मक जवाब, जांच की पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बहाल करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। चुनावी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी बेटी को न्याय दिलाने का सवाल किसी दल के राजनीतिक हित से बड़ा है।

फिलहाल संकेतों की राजनीति शुरू हो चुकी है। यदि आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला और विपक्ष ने इसे संगठित तरीके से उठाया, तो अंकिता प्रकरण चुनाव से पहले सड़क से सदन तक सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि विपक्ष इस मुद्दे पर आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब करता है और सरकार उठते सवालों का जवाब किस तरह देती है।

सुरक्षात्मक कार्यों से बद्दहाल हुई औली सड़क

चमोली (आरएनएस)। नगर में चल रहे भू-स्थिरीकरण और सुरक्षात्मक कार्यों के कारण औली सड़क की स्थिति बद्दहाल बनी हुई है। नवंबर से औली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में पर्यटन सीजन से पहले सड़क की स्थिति नहीं सुधरी तो पर्यटकों को जाम और आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों औली रोड पर जगह-जगह सीवर और ड्रेनेज का कार्य चल रहा है।

नालियों के निर्माण के लिए सड़क की खोदाई की जा रही है जिससे मार्ग पर मिट्टी और मलबे के ढेर लगे हैं। बर्फबारी शुरू होते ही औली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगती है। पहले से संकरी सड़क पर निर्माण कार्य के चलते जाम की समस्या और गंभीर हो सकती है।

स्थानीय सोहन सिंह बैजवाड़ी, अमित कवाण और गिरीश थपलियाल का कहना है कि सुरक्षात्मक कार्यों के कारण सड़क की स्थिति बद्दहाल है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्य पूरा कर सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की। वहीं उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर सड़क की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे।

शिविर में 40 ग्रामीणों के आरंभ की हुई जांच

श्रीनगर गढ़वाल (आरएनएस)। हंस फाउंडेशन सतपुली की ओर कीर्तिनगर ब्लॉक के राईका मोलधार में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 से अधिक ग्रामीणों की आंखों का परीक्षण किया गया। डॉ. अनिल नेगी ने मोतियाबिंद से पीड़ित 10 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया। इनका अब हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली में निशुल्क उपचार किया जाएगा। 15 नेत्र रोगियों को दवा और 20 को चश्मे दिए गए। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रसाद भट्ट एवं ग्राम प्रधान रुचिता देवी कंडारी ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिविरों का आयोजन गरीब व असहाय लोगों के लिए लाभकारी भी होते हैं। संतोष कुमार तथा सपोर्ट स्टाफ रविन्द्र सिंह ने शिविर आयोजन में सहयोग किया।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आखिरी हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो सांध्य दैनिक दून वैली मेल के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

बैन बेअसर, केदारनाथ में रीलबाजों का खेल

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। बाबा केदार के दरबार में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन के इस्तेमाल और रील बनाने पर प्रतिबंध के बावजूद कैमरे चमक रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं और आस्था के इस पवित्र केंद्र को सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बटोरने का मंच बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उसका पालन कौन कराएगा? आखिर जिम्मेदार तंत्र की निगरानी के बावजूद रीलबाजों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं?

केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां लोग बाबा के दर्शन, पूजा-अर्चना और आध्यात्मिक शांति की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए धाम की यात्रा भक्ति से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखावे का जरिया बनती नजर आ रही है। कभी कैमरे के सामने अभिनय, कभी आकर्षक दृश्यों के साथ वीडियो और कभी लाइक व फालोअर बढ़ाने की होड़। इन गतिविधियों ने धार्मिक मर्यादा और व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सबसे बड़ा सवाल प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन का है। यदि धाम में रील बनाने पर रोक है, तो नियम तोड़ने वालों को रोका क्यों नहीं जा रहा? क्या निगरानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है या फिर कार्रवाई के अभाव में प्रतिबंध केवल कागजी आदेश बनकर रह गया है? प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है

और आगे निगरानी के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है।

सिर्फ प्रतिबंध की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं होता। नियम तभी प्रभावी होते हैं, जब उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति खुलेआम नियम तोड़ता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो दूसरे लोगों को भी यही संदेश जाता है कि आदेशों की अनदेखी करने पर कोई खास परेशानी नहीं होगी। केदारनाथ जैसे

◆प्रतिबंध के बावजूद धाम में नहीं धम रहा रील बनाने का सिलसिला जारी
◆आस्था के केंद्र को सोशल मीडिया का मंच बनाने वालों पर कार्रवाई कब
◆जिम्मेदार तंत्र की निगरानी के बावजूद रीलबाजों के हौसले इतने बुलंद कैसे

संवेदनशील धार्मिक स्थल पर ऐसी ढिलाई व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करती है।

सोशल मीडिया के दौर में हर पल को कैमरे में कैद करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। लेकिन क्या हर जगह कैमरा चलाना जरूरी है? धार्मिक स्थलों की अपनी मर्यादा और व्यवस्थाएं होती हैं। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा, पूजा-पद्धति और आध्यात्मिक वातावरण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लोकप्रियता की दौड़ में यदि लोग इन बातों को भूल रहे हैं, तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि धार्मिक संवेदनशीलता की अनदेखी भी है। हालांकि, यह भी जरूरी है कि प्रशासन प्रतिबंध के दायरे और उसके लागू होने की शर्तों को स्पष्ट करे। सामान्य मोबाइल इस्तेमाल, फोटोग्राफी और

प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने के नियमों के बीच भ्रम नहीं रहना चाहिए। नियम स्पष्ट होंगे, तभी उनका निष्पक्ष और प्रभावी पालन कराया जा सकेगा।

केदारनाथ में व्यवस्थाओं की निगरानी करने वाले अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रतिबंध के बावजूद यदि रील बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो प्रशासन को निगरानी व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर स्पष्ट सूचना-पट्ट, नियमित निगरानी और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई जरूरी है। साथ ही, सोशल मीडिया मंचों पर धार्मिक स्थलों के नाम पर लोकप्रियता हासिल करने की होड़ को बढ़ावा देने वालों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हर दृश्य को मनोरंजन और प्रचार की सामग्री में बदलना जरूरी नहीं है। आस्था का सम्मान केवल माथा टेकने से नहीं, बल्कि उस स्थान की मर्यादा और नियमों का पालन करने से भी होता है।

केदारनाथ धाम की गरिमा बनाए रखना प्रशासन और श्रद्धालुओं, दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब प्रतिबंध के बावजूद नियम टूटने की खबरें सामने आती हैं, तो पहला सवाल व्यवस्था से ही पूछा जाएगा। आखिर कब तक आदेश जारी होते रहेंगे और नियम टूटते रहेंगे? बाबा केदार के दरबार में आस्था सर्वोपरि होनी चाहिए, न कि लाइक, व्यूज और फालोअर की भूख। अब जरूरत केवल प्रतिबंध दोहराने की नहीं, बल्कि उसे जमीन पर प्रभावी बनाने की है।

सहसपुर विधायक ने विभिन्न विकास योजनाओं का किया शिलान्यास

संवाददाता

देहरादून। सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर ने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुरक्षा को सुदृढ़ करने और जनसुविधाओं के विस्तार के संकल्प के साथ आज सेलाकुई स्थित अम्बेडकर कॉलोनी में सुरक्षा दीवार तथा वार्ड संख्या 07 में सी.सी. मार्ग (कंक्रीट सड़क) निर्माण कार्य का विधिवत पूजा-अर्चना कर शिलान्यास किया गया। इस दौरान विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा कि क्षेत्र का समग्र, संतुलित एवं सतत विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्रवासियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। सेलाकुई की अम्बेडकर कॉलोनी में प्रस्तावित सुरक्षा दीवार का निर्माण स्थानीय निवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बरसात के दिनों में क्षेत्रवासियों को होने वाली परेशानियों को कम करने तथा संभावित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने में यह निर्माण कार्य सहायक सिद्ध होगा। सुरक्षा दीवार के निर्माण से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में सेलाकुई के वार्ड संख्या 07 में सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र में सड़क संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी। पक्के मार्ग के निर्माण से दैनिक आवागमन सुगम होने के साथ-साथ विद्यार्थियों, बुजुर्गों और अन्य स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। विधायक पुण्डीर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के प्रत्येक वार्ड एवं ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार सड़क, पेयजल, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते समय स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को विशेष महत्व दिया जाता है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि व पार्षद अनिल नौटियाल, नगर अध्यक्ष सेवा भारती, पूर्व प्रधान भगत सिंह राठौर, पार्षद अरशद, श्रीमती नरगिस कश्यप, श्रीमती कल्पना कोली, सिंचाई विभाग के अपर सहायक अभियंता प्रशांत कुमार एवं राजेश कुमार, सहायक अभियंता राजेंद्र सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षित बेरोजगारों का धरना व क्रमिक अनशन जारी

संवाददाता

देहरादून। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का धरना 141 दिन व क्रमिक अनशन 126 दिन में जारी रहा। उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। संगठन के अनुसार, 4 जून से शिक्षा निदेशालय, ननुरखेड़ा, देहरादून में प्रशिक्षित बेरोजगार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आंदोलन के 141दिन पूरे हो चुके हैं, जबकि 126वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी है। वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि लंबे संघर्ष के बावजूद उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पाण्डेय ने कहा कि यह संघर्ष केवल बेरोजगार युवाओं की रोजी-रोटी का सवाल नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की स्थिति और बच्चों के सर्वांगीण विकास से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार खेल महोत्सवों के माध्यम से प्रदेश के नौनिहालों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अनेक सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पदों की कमी बनी हुई है। विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों को खेल प्रशिक्षण और नियमित शारीरिक शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। पाण्डेय ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को निखारने, विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने, अनुशासन विकसित करने तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में योग्य शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। केवल खेल आयोजन कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यालय स्तर पर नियमित प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शारीरिक शिक्षा को उचित स्थान देते हुए प्रदेश के प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री की ओर से मिले आश्वासनों के बावजूद यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता और संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं लाया जाता, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। पाण्डेय ने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है, तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन करने सहित आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करेगा।

केले के छिलके से निकले इन तारों को खाते हैं आप ?

केला खाते समय हममें से अधिकांश लोगों की नज़रें केले की सतह पर लगे उन सफेद रंग के तारों या रेशे पर पड़ती हैं इन तारों को वैज्ञानिक भाषा में ‘फ्लोएम बंडल्स’ कहते हैं। ये तारे केले के अंदरूनी हिस्से से लगे होते हैं और केले की लंबाई में फैले रहते हैं। ये तार दरअसल केले के अंदर मौजूद ऊतक होते हैं जो केले में मौजूद पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। जब हम इन तारों को हटाने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से टूट जाते हैं। अधिकांश लोगों को ये धागे यानी तारें खाने में अस्वादिष्ट लगते हैं। कुछ लोग तो इन्हें पूरी तरह से अलग कर देते हैं। लेकिन क्या ये तारे वाकई में खाने योग्य हैं? क्या इन्हें खाने से कोई नुकसान हो सकता है? आइए जानते हैं।

केले की सतह पर लगे फ्लोएम बंडल्स यानी वे सफेद रंग के फाइबर वाले तार, केवल केले को ही पोषक तत्व नहीं देते बल्कि खाने में काफी फायदेमंद भी होते हैं। इनमें फाइबर, पोटेशियम, विटामिन बी-



6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। साथ ही, इनसे हमारे रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने में भी सहायता मिलती है। इसलिए, केला खाते समय इन फाइबर वाले तारों से डरने की बजाय इन्हें खाना चाहिए।

वास्तव में फ्लोएम बंडल्स से हमें यह भी पता चलता है कि केला पक चुका है या नहीं। इसलिए, केले के ‘तारों’ को खाना चाहिए। केले के साथ इसको खाना

फायदेमंद माना जाता है। फ्लोएम बंडल्समें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है।

फाइबर हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। यह हमारा पाचन तंत्र ठीक रखने का काम करता है।फाइबर से भरपूर फ्लोएम बंडल्स का खाने से हमारा पेट साफ रहता है। यह कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। साथ ही, यह हमारे वजन को भी कंट्रोल रखता है। इसीलिए, केला खाते समय इन फाइबर युक्त तारों को अलग न करें बल्कि खा लें।

पौधों के जरिए शुद्ध करें घर की हवा

अपने घर के आसपास के वातावरण को पौधे लगाने के जरिए हरा-भरा और शुद्ध बनाएं रखने की सलाह हमेशा दी जाती है। एलोवेरा, स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे हवा को शुद्ध करते हैं।

एलोवेरा (घृत कुमारी) कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। घर में लगाए जाने वाले लाभकारी पौधों में से यह एक है। यह ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि एक एलोवेरा का पौधा नौ एयर प्यूरीफायर (हवा को शुद्ध करने वाला उपकरण) के बराबर होता है। यह हर मौसम और मिट्टी में आसानी से लग जाता है।

बैबू (बांस) के पौधे को पर्याप्त सूरज की रोशनी की भी जरूरत नहीं होती और यह घर के अंदरूनी भागों जैसे कमरों आदि



में रखे जाने पर भी आसानी से विकसित होता है। हवा को शुद्ध करने साथ ही यह घर में सौभाग्य भी लाता है। यह वातावरण को रोगाणु मुक्त भी रखता है। कम पानी में भी आसानी से लग जाने वाला यह पौधा नजदीकी पौधों के दुकानों में आसानी से मिल जाता है।

आइवी पौधा अपने रोपण के छह घंटे के भीतर ही हवा को शुद्ध करना शुरू कर

देता है। यह हवा में मौजूद अवशिष्ट कणों को 58 प्रतिशत और हानिकारक विषाक्त कणों को 6० प्रतिशत तक दूर कर देता है।

स्पाइडर पौधा कम धूप में भी अच्छे से प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जाना जाता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टेरीन और गैसोलीन को हटाकर हवा को शुद्ध करता है, जिससे बच्चे और वयस्क आराम से सांस ले सकते हैं। स्नेक पौधा भी सूरज की कम रोशनी में अच्छी तरह से प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। शयनकक्ष में रखे जाने के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यह रात में भी ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। पीस लिली का पौधा हवा में मौजूद हानिकारक कणों और रोगाणुओं को दूर करके हवा शुद्ध करता है।

शब्द सामर्थ्य -063

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :

1. अनुचित, असत्य, जो ठीक न हो 3. बेवजह, बिनाकारण, व्यर्थ 4. हल्कीनींद, चकमा, धोखा 6. शक्कर पानी आदि का मीठा घोल 10. सोते से उठाना, सावधान करना, प्रदीप्त करना 11. चरमसीमा, सीमांत 14. पानी, आंसू 15. बैठा हुआ, विराजित 16. नृत्य 17.

मृतप्राय, मृत्यु के करीब 19. जल, अम्बु 22. उपहार, भेंट 23. खबर, संदेश।

ऊपर से नीचे

1. गणपतिजी, 2. मांगनेवाला, पाने की इच्छा करने वाला 3. मिट्टी के रंग का, मटमैला 5. चला आता हुआ क्रम प्रथा, प्रणाली, रीति-रीवाज, 7. निशाचर, रात में विचरण करने

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

10

11

12

13

14

14

15

16

18

20

17

18

19

24

25

20

26

21

22

23

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 62 का हल

अ	भि	षे	क		प	स		
जा	त		थ	प	थ	पा	ना	
य	र	का	नी		भ्र		र	श्मि
ब	घा	र		क	ष्ट	प्र	द	
	त	ना	त	नी		र्व		ब
अ		मा		ज	मा	त		ल
स	जा					क	ज	रा
बा		बे	स	हा	रा		ग	म
ब	गु	ला		रा	ज	दू	त	

मैथ्री मूवी मेकर्स की नई प्रेम कहानी का शीर्षक जल्द होगा जारी!

दक्षिण भारतीय फिल्म जगत में एक नई प्रेम कहानी दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। फिल्म निर्माता कंपनी मैथ्री मूवी मेकर्स अपनी आगामी रोमांटिक फिल्म का शीर्षक जल्द जारी करने वाली है। इस फिल्म के जरिए अभिनेता श्रीकांत की बेटी मेधा मेका बड़े पर्दे पर अभिनय की शुरुआत करेंगी। फिल्म में जय जस्ती मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जबकि पृथ्वी वनम इस परियोजना के साथ निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं।

फिल्म निर्माताओं ने हाल ही में इसका नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में जय जस्ती और मेधा मेका रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही निर्माताओं ने जल्द ही फिल्म के शीर्षक का खुलासा करने का संकेत दिया है। पोस्टर सामने आने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है।

निर्माताओं ने सामाजिक माध्यम पर पोस्टर साझा करते हुए फिल्म को माइथ्री इन लव' नाम से प्रचारित किया। संदेश में कहा गया कि यह ऐसी प्रेम कहानी है, जो दो किरदारों से शुरू होकर दर्शकों के दिलों तक पहुंचेगी। पोस्ट में जय जस्ती और मेधा मेका का परिचय कराते हुए फिल्म के शीर्षक की घोषणा जल्द करने की बात भी कही गई।

फिलहाल माइथ्री इन लव' फिल्म का प्रचार नाम है। फिल्म का आधिकारिक शीर्षक क्या होगा, इसका खुलासा निर्माताओं की ओर से बाद में किया जाएगा।

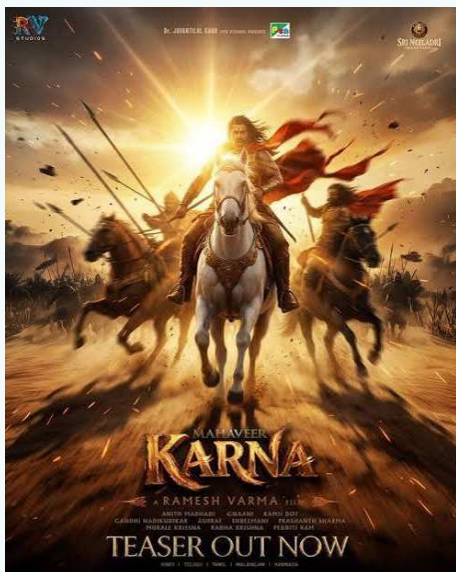
फिल्म की कहानी महेश बाबू पी ने लिखी है, जो मिस शेटी मिस्टर पॉलीशेटी' और आंध्रा किंग तालुक' जैसी फिल्मों से जुड़े रहे हैं। फिल्म को एक रोमांटिक मनोरंजक प्रस्तुति के रूप में तैयार किया जा रहा है। हालांकि, इसकी कहानी और प्रदर्शन की तारीख को लेकर विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

अभिनेता श्रीकांत के बेटे रोशन पहले ही फिल्म जगत में कदम रख चुके हैं और अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के बीच पहचान बना रहे हैं। अब उनकी बेटी मेधा मेका भी अभिनय की दुनिया में प्रवेश करने जा रही हैं। ऐसे में उनकी पहली फिल्म को लेकर दर्शकों और फिल्म जगत की नजरें टिकी हैं।

पृथ्वी वनम के निर्देशन में बन रही इस फिल्म से जय जस्ती और मेधा मेका की नई जोड़ी पहली बार दर्शकों के सामने आएगी। अब सभी को फिल्म के आधिकारिक शीर्षक और आगे जारी होने वाली जानकारी का इंतजार है।

महावीर कर्ण : कर्ण के वचन और शौर्य की गाथा दिखाएगी फिल्म

पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों के शौकीनों के लिए महावीर कर्ण' का टीज़र जारी कर दिया गया है। निर्देशक रमेश वर्मा इस फिल्म के जरिए महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। रमेश वर्मा इससे पहले रवि तेजा की वीरा', अब्बयिथो अम्मायी' और बेल्लमकोंडा श्रीनिवास की राक्षसुडु' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं।



फिल्म के टीज़र की शुरुआत भगवान कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद से होती है। कृष्ण, कर्ण से कहते हैं कि यदि वह पांडवों का साथ चुन लें, तो पूरी दुनिया उन्हें राजा के रूप में पूजेगी। इसके बाद टीज़र में कर्ण के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक दिखाई जाती है। इसमें ब्रह्मास्त्र, कवच और कुंडल से जुड़े प्रसंगों को भी शामिल किया गया है।

टीज़र का समापन कर्ण के उस संकल्प को रेखांकित करने वाले संवाद से होता है, जो किसी भी परिस्थिति में अपना वचन निभाने के लिए जाने जाते हैं। कर्ण के शौर्य, संघर्ष और वचनबद्धता को केंद्र में रखकर तैयार किए गए दृश्यों से फिल्म की कहानी के प्रति उत्सुकता बढ़ी है। फिल्म में धनंजय वर्मा, रोशन, चैतन्य राव और मुरली कृष्ण अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म में बड़े सितारों की मौजूदगी सीमित होने के बावजूद निर्देशक रमेश वर्मा ने आधुनिक तकनीक और भव्य दृश्य संयोजन के माध्यम से इसे प्रभावशाली रूप देने की कोशिश की है। टीज़र में पौराणिक प्रसंगों को बड़े स्तर पर प्रस्तुत करने की झलक मिलती है।

डॉ. जयंतिलाल गाढा के पेन स्टूडियोज के बैनर तले फिल्म प्रस्तुत की जा रही है। इसका निर्माण आरवी स्टूडियोज और नीलाद्री प्रोडक्शंस ने किया है। फिल्म के संवाद श्री मणि ने लिखे हैं। संगीत की जिम्मेदारी ज्ञानी, छायांकन का काम अनित मधादी और संपादन की जिम्मेदारी प्रवीन पुडी ने संभाली है।

महावीर कर्ण' के टीज़र के साथ फिल्म की पौराणिक कथा, कर्ण के चरित्र और आधुनिक तकनीक के मेल को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। अब फिल्म की आगे की झलक और प्रदर्शन तिथि को लेकर जानकारी का इंतजार है।

अगर अच्छा काम नहीं मिलता, तो सिर्फ फ्रेम में खड़े रहने के लिए काम नहीं करती : सम्वेदना सुवालका

अभिनेत्री सम्वेदना सुवालका फिल्म दृश्यम-द कन्क्लूजन (दृश्यम 3) में विजय सालगांवकर की वकील एडवोकेट गायत्री मोहन के रोल में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने दृश्यम टीम की तारीफ करते हुए कहा कि बड़े कलाकार नए कलाकारों को कभी दबाते नहीं हैं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाते हैं। अभिनेत्री ने कहा, फिल्म में सभी कलाकारों के साथ काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। फिल्म में इतने अच्छे कलाकार हैं कि जब हम उनके साथ थड़े होते हैं, तो हम और चमकने लगते हैं। मैं बस अपना काम कर रही थी और वे सभी मुझे उठा रहे थे।

अभिनेत्री ने कहा, कुछ मामलों में मैं सिलेक्टिव हूं। अगर मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिलता है, तो मैं सिर्फ फ्रेम में खड़े रहने के लिए काम नहीं करती हूं। अब जब मैंने इतना काम कर लिया है, तो मैं और भी अच्छे किरदार करना चाहूंगी लेकिन मैं अवसरों को नहीं छोड़ना चाहती हूं। मैं अब बहुत काम करना चाहती हूं।

अभिनेत्री संवेदना सुवालका आगामी फिल्म गुरु में जॉन अब्राहम के साथ नजर आएंगी। जॉन अब्राहम के साथ अपना अनुभव शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कहा, फिल्म गुरु में हम साथ काम कर रहे हैं, जिसे रिबु दासगुप्ता ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में जॉन हीरो वाली छवि दिखाने के बजाय अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। मैं अभी-अभी काम से वापस आई हूं और मुझे बहुत मजा आया।

अभिनेत्री सम्वेदना सुवालका ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि वास्तव में कई



अभिनेताओं को अलग-अलग तरीकों से पहचाना जाता है। कुछ एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते हैं, कुछ कॉमेडी के लिए

जाने जाते हैं और कुछ ऑल-राउंडर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में मैं ऐसा नहीं कहूंगी।

अल्लू अर्जुन की राका में हैं मृणाल ठाकुर? अभिनेत्री ने खुद बताई सच्चाई



बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर पिछले करीब 2 सालों से अल्लू अर्जुन और निर्देशक एटली की महत्वाकांक्षी साईंस-फिक्शन एक्शन फिल्म राका से जुड़ी खबरों

को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, अभिनेत्री ने अब तक फिल्म में अपनी भूमिका को लेकर चुप्पी साध रखी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में मृणाल से फिल्म का हिस्सा होने

के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

मृणाल ने कहा, मैंने पिछले लगभग 9 महीनों में कोई फिल्म साइन नहीं की है। मैं किसी अच्छे और अर्थपूर्ण किरदार का इंतजार कर रही हूं। अब जो भी घोषणा होगी, वह मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर ही होगी और तब मैं इस बारे में बात करना पसंद करूंगी। मेरे पास ऑफर की काफी भरमार है, लेकिन आजकल जो कहानियां बन रही हैं, वह मुझे खास पसंद नहीं आती हैं।

मृणाल ने आगे कहा, मैंने कुछ समय का ब्रेक लेने का फैसला किया है, क्योंकि मैं यह नहीं सोचना चाहती कि मैं हर दिन सेट पर क्यों हूं। इसलिए, मैं सोच-समझकर ऐसी फिल्में साइन करती हूं जिनसे मुझे न सिर्फ प्यार और पहचान मिले, बल्कि क्रिएटिव संतुष्टि भी मिले। जब मैं सोने जाऊं, तो मैं यह नहीं सोचना चाहती कि मैंने बुरा काम किया है। मैं ऐसा काम करना चाहती हूं, जिससे लोग हमेशा मुझे याद रखें।

साल 2026 मृणाल के लिए काफी खास रहा है। दरअसल इस साल उनकी 4 फिल्मों रिलीज हुईं, जो दो दीवाने शहर में, है जवानी तो इश्क होना है, डकैत-अ लव स्टोरी और हाल ही में आई पूजा मेरी जान थी।

दिव्यांगजनों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए चलाया अभियान!

संवाददाता
देहरादून। दिव्यांगजनों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए स्वीप टीम ने जागरूकता अभियान चलाया।

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जनपद देहरादून में समावेशी, सुगम एवं सुलभ मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला स्वीप टीम द्वारा दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने के साथ ही मतदान संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। गांधी शताब्दी अस्पताल, डालनवाला, देहरादून में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के साथ-साथ मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया गया। जिला स्वीप टीम ने दिव्यांगजनों को निर्वाचन में उनकी भागीदारी के महत्व, मतदान प्रक्रिया तथा सुगम, सुलभ एवं समावेशी मतदान की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य दिव्यांग मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना रहा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून के निर्देशन में खंड विकास कार्यालय, डोईवाला में दिव्यांगजनों के लिए मतदाता साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय, समाज कल्याण विभाग एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को मतदाता साक्षरता, निर्वाचन संबंधी सुविधाओं तथा मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की जा रही है। शिविर में जिला स्वीप टीम, देहरादून द्वारा स्टॉल लगाकर जागरूकता अभियान में सक्रिय सहभागिता की जा रही है। टीम के माध्यम से दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति जागरूक करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को बिना किसी बाध 1 के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। इसके लिए दिव्यांगजनों सहित सभी वर्गों की निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।



कांग्रेस का आंदोलन ‘सियासी नाटक’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज होने लगा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव की तैयारी पर भाजपा ने तीखा पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक नाटक करार दिया है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश की जनता पांच साल से कांग्रेस के ऐसे आंदोलनों और राजनीतिक प्रदर्शनों को देखते-देखते ऊब चुकी है। चुनाव करीब आते ही कांग्रेस को सड़क पर उतरने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की याद आने लगी है। भाजपा के इस हमले से साफ है कि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के आंदोलनों को केवल विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति के तौर पर पेश करना चाहता है। दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए जनहित के मुद्दों को सड़क से सदन तक ले जाने की तैयारी में है। ऐसे में न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तीखी हो सकती है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को जनता के बीच जाने और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अधिकार है, लेकिन केवल यात्राओं, धरनों और घेराव से जनसमर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय होने का दिखावा करती है, जबकि जनता के सामने ठोस विकल्प और स्पष्ट कार्ययोजना रखने में विफल रहती है। भाजपा की रणनीति कांग्रेस के आंदोलन को जनाक्रोश के बजाय राजनीतिक अवसरवाद के रूप में प्रस्तुत करने की है। पार्टी यह संदेश देना

चाहती है कि जनता अब केवल नारों और प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाली नहीं है। सरकार के कामकाज और विपक्ष की भूमिका का आकलन जनता अपने अनुभवों के आधार पर करेगी।

कांग्रेस की न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव की तैयारी को सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष के लिए सड़क पर उतरना केवल विरोध दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और

◆न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव पर गरमा गई सियासत
◆भाजपा बोली-पांच साल से एक ही पटकथा देख रही जनता
◆मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक दिखावे पर है कांग्रेस पार्टी का जोर

चुनाव से पहले संगठन में ऊर्जा भरने का अवसर भी है। कांग्रेस की कोशिश है कि सरकार से जुड़े सवालों और जनसमस्याओं को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया जाए। विधानसभा घेराव के जरिये वह यह संदेश देना चाहती है कि विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर चुप बैठने वाला नहीं है। हालांकि, इन आंदोलनों से कितना जनसमर्थन जुटता है, यह उनकी तैयारी, उठाए गए मुद्दों और जनता से जुड़ाव पर निर्भर करेगा।

भाजपा के हमले ने कांग्रेस के सामने भी सवाल खड़ा किया है। यदि कांग्रेस जनता के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि उसकी न्याय यात्रा किन मुद्दों पर केंद्रित है और विधानसभा घेराव से क्या हासिल करने की रणनीति है। केवल सरकार विरोधी नारों से आगे बढ़कर जनता को

ठोस समाधान और वैकल्पिक नीतियां बताना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। वहीं भाजपा के लिए भी चुनौती कम नहीं है। कांग्रेस के आंदोलनों को राजनीतिक नाटक बताना एक बात है, लेकिन जनसमस्याओं पर उठ रहे सवालों का जवाब देना दूसरी। यदि विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई या अन्य जनहित के मुद्दों को उठाता है, तो सरकार को आरोपों का जवाब तथ्यों और अपने कामकाज के आधार पर देना होगा।

उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव के माध्यम से अपनी सक्रियता दिखाना चाहती है, जबकि भाजपा उसके आंदोलन को चुनावी दिखावा बताकर उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। यह टकराव केवल एक यात्रा या घेराव तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने और चुनावी विमर्श पर नियंत्रण बनाने की कोशिश भी है। भाजपा चाहती है कि बहस कांग्रेस के आंदोलनों की मंशा पर केंद्रित रहे, जबकि कांग्रेस सरकार की जवाबदेही और जनसमस्याओं को चर्चा के केंद्र में लाना चाहेगी।

फिलहाल, भाजपा ने कांग्रेस के आंदोलन की धार को राजनीतिक नाटक बताकर कुंद करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने आंदोलन से जनता का कितना समर्थन जुटा पाती है और भाजपा के इस हमले का जवाब किस तरह देती है। चुनावी रण से पहले सड़क पर होने वाली यह सियासी भिड़ंत दोनों दलों की रणनीति और जनाधार की परीक्षा भी बनेगी।

एनपीएस, यूपीएस के विरोध में किया प्रदर्शन

पौड़ी (आरएनएस)। दशहरा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा कीर्तिनगर की ओर से केंद्र और राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं (एनपीएस/यूपीएस) के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने एनपीएस/यूपीएस का रावण बनाया और उसका दहन किया। इसमें विभिन्न विभागों के कार्मिकों के साथ ही उनके बच्चे भी शामिल हुए।

गढ़वाल मंडल महासचिव राजीव उनियाल ने सभी कर्मचारियों को 2 नवंबर को देहरादून में होने वाले सचिवालय घेराव और गर्जना रैली में पूरी एकजुटता के साथ शामिल होने का आह्वान किया। टिहरी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप मैठाणी ने कहा कि सरकार निरंतर पुरानी पेंशन की मांग को नजरअंदाज कर कर्मचारियों का शोषण कर रही है जिसे बदार्श नहीं किया जाएगा।

ब्लॉक अध्यक्ष कीर्तिनगर सुरजीत लिंगवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में सरकार को इसका बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवप्रयाग दीपक मियां, जगमोहन पुंडीर और राहुल कुमार, जगमोहन पुंडीर, राहुल कुमार, विनोद चौहान, सोहन कोहली, अमित नौडियाल, दीपक मियां मौजूद रहे।

खराब पैचवर्क जेसीबी से उखाड़ा, ऑफिस इंचार्ज और निर्माण फर्म को नोटिस

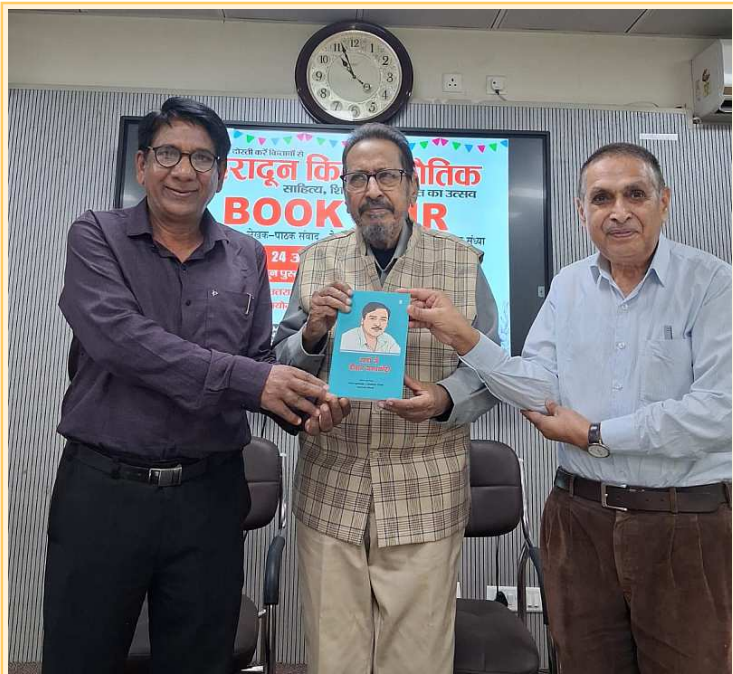
चमोली(आरएनएस)। कर्णप्रयाग-गैरसैंण हाईवे पर गैरसैंण बाजार के समीप सलियाणा बेंड के पास किए गए पैचवर्क की गुणवत्ता में कमी और डामर उखड़ने की शिकायतों पर लोनिवि (एनएच) ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिशासी अभियंता ओंकार पांडेय और अवर अभियंता ने मौके पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान किलोमीटर 186 पर खराब गुणवत्ता में बिछाई गई बीसी (बिटुमिनस कंक्रीट) की परत को जेसीबी से उखड़वाया गया। विभाग ने संबंधित ऑफिस इंचार्ज और निर्माण फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने और कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करने

के मामले में संबंधित सहायक अभियंता से भी तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है।बीते दिनों आपातकालीन मरम्मत कार्य के तहत एनएच की ओर से पांडुवाखाल से कर्णप्रयाग तक (किलोमीटर 171 से 235) बीएम (बिटुमिनस मैकडम) से पैचवर्क कराया गया था।जनप्रतिनिधियों और नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण की ओर से कुछ स्थानों पर डामर उखड़ने की शिकायतें की गई थीं जिसके बाद विभाग ने निर्माण की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण पर सवाल उठाए।

इस पर लोनिवि (एनएच) ने मौके का निरीक्षण किया तो शिकायत सही मिली। किमी 186 पर बिछाया गया डामर उखड़वाया गया। अधिशासी अभियंता ने

संबंधित फर्म को हॉटमिक्स प्लांट पर बिटुमेन की मात्रा, एग्रीगेट ग्रेडिंग, मिश्रण की समरूपता और तापमान के साथ बिछाने के निर्देश दिए। उन्होंने फर्म संचालक को कार्य के परीक्षण और सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद ही भुगतान की बात कही। ईई ने कहा कि डामर की घटिया गुणवत्ता पर ऑफिस इंचार्ज और निर्माण फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सहायक अभियंता से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता में लापरवाही बदार्श नहीं की जाएगी। नोटिस के निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सू- दोकू क्र.063								
	6	3		8		1		4
8			3		4		7	
	4			5		8		
3		8			1		4	
	1			4		9		7
		4			2		1	
1				3		4		8
	8		2		9		3	
		9		1		2		5
नियम		सू-दोकू क्र.62 का हल						
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है। 2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है। 3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।		6	7	9	2	4	5	3
		2	1	8	3	7	6	9
		7	6	4	5	2	8	1
		3	8	1	6	9	7	2
		9	2	5	4	1	3	8
		8	3	7	9	6	4	5
		5	4	2	8	3	1	7
		1	9	6	7	5	2	4
		4	5	3	1	8	9	6



‘यादों में दीवान नगरकोटी’ पुस्तक का अनावरण

संवाददाता
देहरादून। ‘यादों में दीवान नागकोटी’ पुस्तक का अनावरण कर शोध और पत्रकारियों में उनके योगदान को याद किया। आज यहां दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में शोधार्थी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता दीवान नगरकोटी पर केंद्रित स्मृति पुस्तक ‘यादों में दीवान नगरकोटी’ का अनावरण किया गया। पुस्तक में उनके साधियों के संस्मरणों के साथ उनके लेख और दुर्लभ छायाचित्र संकलित हैं। वक्ताओं ने दीवान नगरकोटी के शोध, पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को याद करते हुए उन्हें उत्तराखंड के सामाजिक सरोकारों से जुड़ी बौद्धिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। पुस्तक का संपादन अरुण कुकसाल, जगमोहन रौतेला और चन्द्रशेखर तिवारी ने किया है। इस अवसर पर गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ में निदेशक रहे और दून पुस्तकालय एवं शोध के वर्तमान अध्यक्ष प्रो. बी.के. जोशी ने दीवान नगरकोटी के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया। उन्होंने कहा, दीवान नगरकोटी हमेशा हमारे परिवार के सदस्य की तरह थे। गिरि संस्थान में उत्तराखंड के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में वे मेरे शोध सहयोगी रहे। पर्वतीय पृष्ठभूमि की गहरी समझ रखने वाले इस विनम्र व कर्मठ व्यक्ति असामयिक निधन हम सबके लिए बड़ा आघात रहा। प्रो. जोशी ने बताया कि शोध परियोजना में उत्तराखण्ड के कई युवा उनकी शोध टीम में जुड़े थे। इनमें दीवान नगरकोटी के अलावा प्रदीप टप्टा, चन्द्रशेखर तिवारी, अरुण कुकसाल, मंगल सिंह आदि शामिल थे। उन्होंने कहा कि मित्रों द्वारा प्रकाशित यह स्मृति ग्रंथ दीवान की यादों को सहेजने का सार्थक प्रयास है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका रुझान पत्रकारिता की ओर भी रहा उन्होंने अल्मोड़ा में पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके जीवन की यह यात्रा शोध से पत्रकारिता और फिर सामाजिक कार्य तक फैली रही, जिसमें पहाड़ के समाज और उसकी समस्याओं के प्रति प्रतिबद्धता बनी रही।

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’.

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

की स्थिति जैसे सवाल चुनावी बहस के केंद्र में बने रहेंगे।
भाजपा का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरने में कितना सफल होगा, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 2027 की लड़ाई अब केवल सरकार बनाम विपक्ष नहीं रह गई है। यह जनता के सामने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने और चुनावी विमर्श पर पकड़ बनाने की लड़ाई भी बनती जा रही है।

...और भाजपा को याद आई ‘वोट चोरी’.

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

लेकिन जनता के लिए असली मुद्दा यह नहीं है कि कौन-सी पार्टी किस पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। असली सवाल यह है कि क्या प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा? लोकतंत्र में वोट किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, जनता का अधिकार है। इस अधिकार पर सवाल उठे तो उसका जवाब नारों से नहीं, निष्पक्ष जांच, पारदर्शी प्रक्रिया और ठोस प्रमाणों से दिया जाना चाहिए।

परम संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

दिए। परम संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने प्रभु को पाने के लिए ध्यान अभ्यास पर जोर दिया। उन्होंने फरमाया कि ध्यान अभ्यास के माध्यम से परम संत कृपाल सिंह महाराज के अपने आपको जानने और पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता बताया है उस पर चलने से हमारे कदम प्रभु की तरफ चल पड़ते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रभु परमेश्वर हमारे भीतर है लेकिन हम जिंदगी के कामकाजों में इतना व्यस्त हैं कि हम उनको देख, पहचान नहीं पाते हैं लेकिन जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं तो मन माया के परदे हटने शुरू हो जाते हैं और हमारे कदम प्रभु की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्होंने संगत को ज्यादा से ज्यादा आश्रम आने के लिए प्रेरित किया और कहा कि जब भी हम आश्रम आयेंगे तो हमें शांति सकून मिलता है और हमारा ध्यान सिमरन प्रभु की तरफ लगने लगता है और हमारा जीवन बेहतर होने लगता है।

जनजातीय इतिहास और संस्कृति से रबर हुए छात्र-छात्राएं

संवाददाता
देहरादून। भ्रमण के दौरान छात्रों ने जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कलाओं, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक धरोहरों से संबंधित प्रदर्शित सामग्री का अवलोकन किया।

आज यहां सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज, साहिया के इतिहास विभाग एवं ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग के छात्र-छात्राओं ने देहरादून स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थान एवं आदिवासी संग्रहालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को जनजातीय समाज के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं, लोककला एवं पारंपरिक जीवनशैली से परिचित कराना और पुस्तकीय ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ना रहा।

भ्रमण के दौरान छात्रों ने जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कलाओं, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक धरोहरों से संबंधित प्रदर्शित सामग्री का अवलोकन किया। इसके माध्यम से उन्हें जनजातीय समाज की विशिष्ट पहचान,



सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक जीवनशैली को समझने का अवसर मिला। इस शैक्षणिक भ्रमण में छात्रों ने जनजातीय परंपराओं एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के महत्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग के छात्रों के लिए यह भ्रमण विशेष रूप से उपयोगी रहा। उन्होंने पारंपरिक कला, शिल्प और विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों को करीब से देखा और जनजातीय संस्कृति में कला के महत्व को समझा। इतिहास विभाग के छात्रों को जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक एवं सामाजिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण

जानकारियां प्राप्त हुईं। इस प्रकार भ्रमण ने दोनों विभागों के छात्रों को अपने विषयों से संबंधित ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से समझने का अवसर प्रदान किया।

शैक्षणिक भ्रमण में इतिहास विभाग की प्राध्यापक डॉ. रीना रांगड़ और ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग के प्राध्यापक भरत सिंह के मार्गदर्शन में छात्रों ने प्रतिभाग किया। भ्रमण में अंजू, कशिश तोमर, बनिता, काजल, अनीता, शकुंतला, मानसी नेगी, रिया नेगी, मनीष चौहान, अंकित, मानसी बिष्ट, तनिषा और निशा वर्मा सहित अन्य छात्र-छात्राएं शामिल रहे।

रोडवेज कर्मियों का कार्य बहिष्कार, दिया धरना

संवाददाता
देहरादून। अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने तीनों मंडलों में कार्य बहिष्कार कर धरना दिया।

आज यहां कर्मचारी यूनियन ने उत्तराखण्ड सरकार और निगम प्रबन्धन की उत्तराखण्ड की जनता व कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही नितियों के विरोध में प्रदेश के तीनों मण्डलों (देहरादून, कुमाऊं मण्डल, टनकपुर मण्डल) में विशाल धरना प्रदर्शन किया



गया। यूनियन के अध्यक्ष कमल पपने ने कहा कि खेद की बात यह रही कि संगठन ने 6 अक्टूबर को सात सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था किन्तु निगम प्रबन्धन ने समय रहते वार्ता नहीं बुलाई, जिससे सभी बिन्दुओं पर सकारात्मक

चर्चा उपरान्त सहमती बन पाती ऐसी दशा में यूनियन ने विवश होकर धरना कार्यक्रम किया गया तथा नैनीताल मण्डल के सभी डिपों तथा कार्यालालाएं टनकपुर मण्डलों को मिलाकर कुल 1500 कर्मचारियों ने भागीदारी की देहरादून मण्डल में आईएसबीटी पर लगभग 500 यूनियन सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरेन्द्र कुमार, उदयवीर सिंह, ने कार्यक्रम का संचालन किया।

रामलीला प्रांगण में नवनिर्मित टीन शेड का विधायक ने किया उद्घाटन

संवाददाता
देहरादून। विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर ने अपर कण्डोली में रामलीला प्रांगण में नवनिर्मित टीन शेड का विधिवत उद्घाटन किया।

आज यहां सहसपुर विधायक सहदेवह सिंह पुण्डीर द्वारा ग्राम पंचायत कण्डोली अपर में विधायक निधि के अंतर्गत 02 लाख की लागत से रामलीला प्रांगण में नवनिर्मित टीन शेड का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस निर्माण कार्य के होने से स्थानीय लोगों को रामलीला एवं अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर ने कहा कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास तथा क्षेत्रवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में जनसुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रामलीला एवं अन्य सांस्कृतिक आयोजन हमारी समृद्ध भारतीय परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं



और सामाजिक एकता के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। ऐसे आयोजनों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास होने से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलती है तथा नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। रामलीला प्रांगण में टीन शेड के अवशेष निर्माण कार्य के पूर्ण होने से आयोजनों के संचालन में सहूलियत मिलेगी और स्थानीय जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल विकास कार्यों को स्वीकृति दिलाना ही नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर आमजन तक उनका लाभ पहुंचाना भी है। सड़क, पेयजल, जल निकासी, शिक्षा,

स्वास्थ्य तथा सामुदायिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को निरंतर गति प्रदान की जा रही है। साथ ही, विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी संकल्प के साथ सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में समग्र, संतुलित एवं सतत विकास की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्रवासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप जनसुविधाओं का विस्तार हो और प्रत्येक गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। इस कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य कंचन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मेघ सिंह, मण्डल महामंत्री अनुप सेमवाल समेत समस्त भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने नशामुक्त उत्तराखण्ड वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और पुलिस की नहीं, पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री



संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ग्राउंड, ओएनजीसी, देहरादून में ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित ड्रग फ्री उत्तराखण्ड वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नशामुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं सहित सभी प्रतिभागियों से नशामुक्त उत्तराखण्ड के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशामुक्त उत्तराखण्ड वॉकथॉन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और स्वस्थ एवं सशक्त उत्तराखण्ड के

निर्माण का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण अभियान है। इस प्रकार के आयोजनों से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ने के साथ ही युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने इस पहल के लिए ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों, आयोजकों एवं विशेष रूप से देवेन्द्र सिंह बिष्ट की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ ही उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। जिस युवा के हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिसे खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए और अपने परिश्रम से भविष्य संवारना चाहिए, यदि

वह नशे की गिरफ्त में आ जाता है, तो उसके सपनों के साथ ही परिवार की उम्मीदें भी प्रभावित होती हैं। इसलिए युवाओं को नशे से दूर रखकर उनकी ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। युवाओं को अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नशे से दूर रहने के लिए खेल, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। अच्छी संगति, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहने के साथ ही अपने साथियों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और पुलिस के प्रयासों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

पहाड़ी से मलबा गिरने से महिला श्रमिक सहित दो लोगों की मौत!

हमारे संवाददाता

नैनीताल। भवाली क्षेत्र के मेहरागांव में बीती शाम निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। दीवार बनाने का काम कर रहे मजदूरों के ऊपर अचानक पहाड़ी से मलबा गिर गया। मलबे में दबने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूर को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भवाली पहुंचाया।

क्षेत्र के मेहरागांव में बीती शाम निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी से मलबा गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया। हादसा दीवार निर्माण के दौरान हुआ। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने मौके पर हंगामा करते हुए ठेकेदार को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी भवाली पहुंचाया। पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि मेहरागांव में एक निर्माण साइट पर दीवार बनाने का काम चल रहा था। गुरुवार शाम करीब छह बजे अचानक पहाड़ी से मलबा मजदूरों के ऊपर गिर गया। मलबे में दबने से गौरी देवी (38) पत्नी महेंद्र कुमार, मूल निवासी लालकुआं और हाल निवासी निशौला, भीमताल तथा हरीश थापा (18) पुत्र दीपक थापा निवासी नेपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, नेपाल निवासी नेत्र सिंह घायल हो गया।



एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह लापरवाही प्रतीत हो रही है। देर शाम फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार, परिजनों की तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कूड़े में नवजात सहित दो बच्चिया लावारिस मिली

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। जिले में दो मासूम बच्चियों को लावारिस छोड़ने के मामले सामने आए हैं। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में भगत सिंह चौक के पास कूड़े के ढेर में करीब सात दिन की नवजात बच्ची मिली। वहीं, नगर कोतवाली क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस के पास करीब एक साल की बच्ची लावारिस हालत में मिली। दोनों बच्चियों को पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने संरक्षण में लेकर अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार भगत सिंह चौक के पास कूड़े के ढेर से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर राहगीर रुक गए। पास जाकर देखने पर करीब सात दिन की नवजात बच्ची वहां पड़ी मिली। बच्ची को इस हालत में देखकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। समाजसेवी वंदना गुप्ता ने बच्ची को गोद में उठाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम की मदद से 108 एंबुलेंस के जरिए बच्ची को महिला अस्पताल पहुंचाया। दूसरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पोस्ट ऑफिस के पास करीब एक साल की बच्ची लावारिस हालत में मिली। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्ची को संरक्षण में लेकर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस स्थान पर बच्ची मिली, वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। दूसरी बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन की निगरानी में रखा गया है।

महिला न्यायिक अधिकारी के साथ अभद्रता में मुकदमा दर्ज, चालक गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। महिला न्यायिक अधिकारी से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस सांय के समय डालनवाला क्षेत्र की एक सरकारी कालोनी से न्यायिक अधिकारी ने एक कम्पनी की कैब सौड़ा सरोली जाने के लिए बुक की थी। आरोप है कि रास्ते में कैब चालक मोहन खत्री निवासी आर्केडियाग्रांट पटेलनगर ने कहा कि यात्रा नौ किलोमीटर लम्बी है तो किराया दोगुना लगेगा। अधिकारी ने चालक से कहा कि वह रुपये वहीं देंगी जो कम्पनी ने बुकिंग

के दौरान तय किया था। इस पर महिला न्यायिक अधिकारी ने कम्पनी के अधिकारी से फोन पर वार्ता की अधिकारी ने



आश्वासन दिया किया वह चालक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आरोप है कि इसके बाद चालक उन्हें रास्ते में एक

सुनसान गली में ले गया। यह गली आगे से बन्द थी। वह उनसे बदसलूकी करने लगा। वहां खड़े गार्ड ने चालक से पूछा कि क्या बात हो गयी है तो उसने कहा कि मैडम को रास्ता बताना चाहिए था। गार्ड ने कहा कि रास्ता तो गुगल मैप में तो आता है। इस पर चालक गार्ड से लड़ने लगा। कुछ देर बाद वह गाड़ी से उतरा और राइड कैंसल कर दी। डालनवाला कोतवाली विनोद सिंह गुसाईं ने बताया कि अधिकारी के कोर्ट मोहर्रि को फोन पर सूचना दी। चीता पुलिस आरोपी चालक को हिरासत में लेकर थाने आ गये। पुलिस ने कोर्ट मोहर्रि की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कार से तमंचा लहराने वाले दो सगे भाईयों सहित 3 युवक गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। कार के बाहर तमंचा लहराने वाले दो सगे भाईयों सहित तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल एक वीडियो, जिसमें राजपुर रोड में स्विफ्ट डिजायर कार में सवार व्यक्ति द्वारा खुलेआम कार से बाहर तमंचा लहराया जा रहा था, उक्त व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार हथियार प्रदर्शित करने से आमजन में भय व असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो रहा था। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा कार सवार व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल

वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस कर वाहन स्वामी के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु थाने लाया गया, जिससे पूछताछ व जांच में तथ्य प्रकाश में आये की वीडियो में कार के बाहर लहराया जा रहा हथियार असल में एक खिलौना पिस्टल थी, जिसे कार सवार युवकों द्वारा दशहरा मेले से



खरीदा गया था, जांच में भी वीडियो में दिख रहा हथियार खिलौना होना पाया गया। परंतु कार सवार युवकों द्वारा

सार्वजनिक मार्ग पर किये गये इस प्रकार के कृत्य से आमजन में भ्रम व डर का माहौल बनने तथा सोशल मीडिया पर

कानून व्यवस्था की छवि को प्रभावित करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

सोशल मीडिया पर रील व प्रसिद्धि पाने के लिए इस प्रकार का कार्य न करें, इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना आचरण करने पर पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पूछताछ में उन्होंने अपने नाम शंशाक कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी डीएल रोड, डालनवाला, अक्षय कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी डीएल रोड, डालनवाला, अर्पित गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी सिमेंट रोड, डालनवाला बताया।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटेर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार
समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटेर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।